दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अप्रैल (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 नए अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का किया शुभारंभ 3
- राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के लिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ 3
- पाटन में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ 4
- विज्ञान की समझ आसान बनाने के लिये की गई विज्ञान पार्क की स्थापना 4
- देश में सबसे कम बेरोज़गारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अव्वल 5
- राज्य के तीन फेंसिंग खिलाड़ी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिये चयनित 5
- हरियाली प्रसार योजना 6
- कवर्धा में सी-मार्ट का शुभारंभ 6
- राज्य में स्थापित होंगे लगभग 1000 परिवहन सुविधा केंद्र 7
- झलमलको लया-लयोर गोटुल रच्चा उत्सव 7
- शिवरीनारायण में राज्यस्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ 8
- बारनवापारा अभयारण्य को मिला नया स्वरूप 8
- रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण 9
- राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत शिवरीनारायण में प्रथम चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण 9
- छत्तीसगढ़ के हिस्से फिर राष्ट्रीय पुरस्कार 10
- छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू 11
- मुख्यमंत्री ने किया 'आईना-ए-छत्तीसगढ़' पुस्तक का विमोचन 11
- मुख्यमंत्री ने किया 'आईना-ए-छत्तीसगढ़' पुस्तक का विमोचन 11
- राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, 2022 12
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना 12
- छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को मिला राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 13
- छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को मिली जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता 13
- छत्तीसगढ़ में 9240 करोड़ रुपए लागत की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास 14
- राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 14
- 'मोर गाँव मोर पानी' अभियान 15
- सीएसआई-एसआईजी का ई-गवर्नेंस अवार्ड 15
- कॉमनवेल्थ और एशियाड में उतरेंगी छत्तीसगढ़ की आकर्षि 16
- सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाएँ पुरस्कृत 16
- छत्तीसगढ़ को मलेरिया के मामलों में कमी के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया सम्मानित 17
- स्वदेश दर्शन योजना: ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट पहला फेज पूर्ण 17
- राज्यपाल ने किया छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर 18
- छत्तीसगढ़ पुलिस के 11 जवान शूरवीर सम्मान से सम्मानित 18
- हैबियस कॉर्पस रिट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्त्वपूर्ण निर्णय 19
- तीनदिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ 19
- अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा 'माटी पूजन दिवस' 20
- हथखोज में रेल इंडस्ट्रियल पार्क तथा भिलाई में विभिन्न अधोसंरचनाओं का लोकार्पण 20
- राज्य में खुलेंगे 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय 21
- छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र 21

नोट :

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 नए अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 4 नए राजस्व अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- अभी तक छत्तीसगढ़ में कुल 96 अनुविभाग तथा 179 तहसीलें थीं। 4 नए अनुविभाग से अब प्रदेश में कुल 100 अनुविभाग तथा 23 नई तहसीलों के गठन से अब प्रदेश में कुल 202 तहसीलें हो गई हैं।
- नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों के प्रारंभ होने से शासकीय योजनाओं के सुचारु रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी।
- मुख्यमंत्री ने जगदलपुर ज़िले में तोकापाल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले में मरवाही, सूरजपुर ज़िले में भैयाथान तथा गरियाबंद ज़िले में मैनपुर अनुविभाग का शुभारंभ किया।
- इसी तरह मुख्यमंत्री ने जिन 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया, वे हैं-
- सीपत और बोदरी (ज़िला- बिलासपुर)
- सकोला (कोटमी) (ज़िला- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)
- अड़भार (ज़िला- जांजगीर-चांपा)
- सरिया और छाल (ज़िला- रायगढ़)
- बरपाली, अजगरबहार और पसान (ज़िला- कोरबा)
- चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली (ज़िला- बलरामपुर-रामानुजगंज)
- बिहारपुर (ज़िला- सूरजपुर)
- सुहेला और भटगाँव (ज़िला- बलौदाबाज़ार-भाटापारा)
- अहिवारा (ज़िला- दुर्ग)
- नांदघाट (ज़िला- बेमेतरा)
- सरोना (ज़िला- उत्तर बस्तर कांकेर)
- बारसूर (ज़िला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा)
- कुटरू और गंगालूर (ज़िला- बीजापुर)
- छोटे डोंगर और कोहकामेटा (ज़िला- नारायणपुर)

राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के लिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

31 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निर्धारित समय-सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल के माध्यम से नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई समेत अन्य राजस्व कार्यों की मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय समेत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत् मानिटरिंग की जा सकती है।
- नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई की समय-सीमा के बाहर के अनिराकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु भुइयां सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल की व्यवस्था की गई है।
- प्रकरणों का समय पर निराकरण हो, इसके लिये मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिव राजस्व विभाग, संचालक भू-अभिलेख, संभाग आयुक्त एवं ज़िला कलेक्टर के स्तर से सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी।

पाटन में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

1 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के पाटन में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 'हमर लैब' का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3,000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ होंगे।
- इन यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलिएंस में काफी आसानी होगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पब्लिक हेल्थ यूनिट में पाटन के लोगों को टेस्ट कराने में काफी सुविधा होगी। इससे यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में काफी मदद मिलेगी।

विज्ञान की समझ आसान बनाने के लिये की गई विज्ञान पार्क की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

1 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की महिला वैज्ञानिक जे.के. राय ने बताया कि विज्ञान को रुचिकर और आसान बनाने के लिये छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा विद्यालयीन छात्रों के लिये विद्यालय परिसर में विज्ञान पार्क की स्थापना की गई है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के विज्ञान लोकव्यापीकरण योजना के अंतर्गत राज्य में विज्ञान के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विद्यालयीन छात्र-छात्राओं में खेल-खेल में विज्ञान प्रादर्शों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सीखने तथा समझने के लिये विज्ञान पार्कों की स्थापना की गई है।
- राज्य के सभी ज़िलों में परिषद के द्वारा विज्ञान पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- इन पार्कों के माध्यम से विद्यार्थी खेल-खेल में विज्ञान के विभिन्न आयामों को समझ पाएंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में उपयोगी वैज्ञानिक तथ्यों की समझ व दृष्टिकोण, विश्लेषणात्मक सोच तथा रचनात्मक प्रतिभा विकसित होगी।
- विज्ञान पार्क की स्थापना बी.एम. बिरला साइंस सेंटर, बिरला आर्कियोलॉजिकल एवं कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रभाग, हैदराबाद के माध्यम से उनके मापदंड के अनुरूप की गई है।
- इन साइंस पार्कों में विद्यालयीन विज्ञान पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित चलित प्रादर्श स्थापित किये गए हैं। इन प्रादर्शों के माध्यम से विद्यार्थी पाठ्यक्रम में सम्मिलित विज्ञान के सिद्धांतों को आसानी से समझ पा रहे हैं।
- इन प्रादर्शों में गुरुत्व केंद्र सिद्धांत को प्रदर्शित करने हेतु एंटी ग्रेविटी कोण, जड़त्वाघूर्ण के सिद्धांत हेतु रैस द रोलर, पेंडुलम के सिद्धांत पर पेंडुलम पैटर्न्स, न्यूटन के सिद्धांत पर न्यूटन क्रेडल, ध्वनि तरंग के सिद्धांत हेतु जाइलोफोन, कोणीय संवेग को प्रदर्शित करने हेतु ब्लैक होल, 2डी एवं 3डी सिद्धांत हेतु स्प्लीट पर्सनलिटी एवं कोविड-19 हेतु कोरोना वायरस प्रदर्शन बोर्ड आदि शामिल हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 12 साइंस पार्क स्थापित किये गए हैं, जिसमें रायपुर में 2, दुर्ग, नारायणपुर, धमतरी, जाँजगीर-चांपा, बलौदाबाज़ार, रायगढ़, महासमुंद, कोंडागाँव एवं बिलासपुर में एक-एक साइंस पार्क स्थापित हैं।
- हाल ही में दुर्ग ज़िले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाउवारा में साइंस पार्क की स्थापना की गई है तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा में आउटडोर-इनडोर विज्ञान पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

देश में सबसे कम बेरोज़गारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अव्वल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी संगठन द्वारा जारी किये गए बेरोज़गारी के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार मार्च माह में सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है।

प्रमुख बिंदु

- नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर (0.6 प्रतिशत) पर पहुँच गई है। देश में बेरोज़गारी दर 7.5 प्रतिशत है। शहरी बेरोज़गारी दर 8.5 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोज़गारी दर 7.1 प्रतिशत है।
- 2 अप्रैल, 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोज़गारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1 प्रतिशत तथा हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत रही।
- छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गाँवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है।
- इसी मॉडल के अंतर्गत गाँवों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये सुराजी गाँव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए-नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोज़गारी दर में लगातार गिरावट आ रही है।
- कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही, तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही।
- छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 वर्षों में 12 से 15 लाख रोज़गार के नए अवसरों का निर्माण करने के लिये रोज़गार मिशन का संचालन किया जा रहा है।

राज्य के तीन फेंसिंग खिलाड़ी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में फेंसिंग जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिये छत्तीसगढ़ के तीन खिलाड़ियों- सुखम निंगथौबा, के. डेनी सिंह और एस.एन. शिवा मगेश का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ के इन तीनों खिलाड़ियों का चयन हरियाणा के सोनीपत में 25 से 28 दिसंबर, 2022 तक आयोजित 29वीं जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप (बालक एवं बालिका) में व्यक्तिगत इवेंट में पदक प्राप्त करने पर किया गया है।
- इस चैंपियनशिप के फॉइल इवेंट में सुखम निंगथौबा एवं के. डेनी सिंह ने क्रमशः रजत एवं कांस्य पदक वहीं एस.एन. शिवा मगेश ने ईपी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था।

नोट :

- गौरतलब है कि इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन के तत्वावधान में यूनाइटेड अरब अमीरात फेंसिंग महासंघ द्वारा जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप (बालक एवं बालिका) का आयोजन दुबई हमदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
- इस चैंपियनशिप में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय जूनियर एवं कैडेट (बालक एवं बालिका) फेंसिंग टीम की 47 सदस्यीय फेंसिंग टीम भेजी जा रही है।
- छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एवं वर्तमान में सदस्य समीर खान को फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय जूनियर एवं कैडेट फेंसिंग टीम का टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है।

हरियाली प्रसार योजना

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित 'हरियाली प्रसार' योजना के अंतर्गत तीन वर्षों (2019, 2020 तथा 2021) में 83 लाख 31 हज़ार पौधों का रोपण किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में एक हज़ार 600 हेक्टेयर रकबा, 2020-21 में 3 हज़ार हेक्टेयर रकबा तथा 2021-22 में 2 हज़ार 800 हेक्टेयर रकबा (कुल 7 हज़ार 400 हेक्टेयर रकबा) हरियाली से आच्छादित हुआ।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 18 लाख 56 हज़ार पौधों, वर्ष 2020-21 में 33 लाख 80 हज़ार पौधों तथा वर्ष 2021-22 में 30 लाख 95 हज़ार पौधों का रोपण किया गया है।
- हरियाली प्रसार योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 10 हज़ार 497 हितग्राही, वर्ष 2020-21 में 20 हज़ार 16 हितग्राही तथा वर्ष 2021-22 में 13 हज़ार 651 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।
- इस योजना के अंतर्गत सागौन, बाँस, खम्हार, आंवला, शीशम, चंदन, मीलिया-डुबिया, क्लोनल नीलगिरि, टिशू कल्चर बाँस, टिशू कल्चर सागौन, आम, कटहल, मुनगा, सीताफल एवं अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि हरियाली प्रसार योजना के तहत कृषकों की स्वयं की भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने और हरियाली को बढ़ाने के लिये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रति हितग्राही 50 से 5 हज़ार तक पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी देखरेख के लिये अनुदान के रूप में आंशिक राशि भी उपलबध कराई जाती है। इससे कृषकों को लगभग 30 हज़ार रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष का लाभ अर्जित हो सकेगा।

कवर्धा में सी-मार्ट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में सी-मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई जैसे बड़े शहरों की तर्ज़ पर कवर्धा में सी-मार्ट की स्थापना की गई है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे विक्रय करने हेतु एक मंच प्रदान करने व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सी-मार्ट की स्थापना कर रही है।
- कवर्धा ज़िले के महिला समूह अपना सामान विक्रय किये जाने हेतु सी-मार्ट में ला सकते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नगर पालिका परिषद, कवर्धा) द्वारा केनरा बैंक कवर्धा के माध्यम से 10 लाख रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई है।

नोट :

- इस सी-मार्ट का संचालन दीपांजलि महिला स्व-सहायता समूह कवर्धा द्वारा किया जाएगा। सी-मार्ट में दीपांजलि महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्री व दैनिक उपयोग की सामग्री का विक्रय किया जाएगा।
- यहाँ महिलाओं द्वारा तैयार की गई बड़ी, बिजौरी, सेवई, आलू चिप्स, मशाला, हल्दी, मिर्ची, गोबर गमला, चावल आटा, दलिया, गेहूँ आटा, पापड़, मुरकु, फिनाइल सहित अन्य सामग्री का विक्रय किया जाएगा।

राज्य में स्थापित होंगे लगभग 1000 परिवहन सुविधा केंद्र

चर्चा में क्यों ?

7 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिये राज्य भर में लगभग 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की प्रक्रिया को मंज़ूरी मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिये राज्य भर में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 26 जनवरी को घोषणा की थी।
- इस दौरान परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप को अनुमोदित कर आगे की कार्यवाही के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1000 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना से करीब पाँच हज़ार युवाओं के रोज़गार सृजन की संभावना भी बनेगी।
- 31 मार्च, 2021 को जारी भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240(अ) के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिये परिवहन सुविधा केंद्र को अधिकृत किया जा सकता है। इस परिकल्पना को रोज़गारोन्मुखी स्वरूप देने के लिये छत्तीसगढ़ में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- परिवहन सुविधा केंद्रों में लर्निंग लाइसेंस के अलावा अन्य परिवहन संबंधी सेवा के लिये आवेदन किया जा सकेगा। इससे जहाँ आम जनता को आसानी से और घर से निकट परिवहन संबंधी सेवाएँ उपलब्ध होंगी, वहीं शिक्षित युवा बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा। मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केंद्रों में विभिन्न सेवाओं के लिये शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
- अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिये आवेदन करते रहे हैं, जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। अब परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिये अनधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।

झलमलको लया-लयोर गोटुल रच्चा उत्सव

चर्चा में क्यों ?

8 अप्रैल, 2022 को छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर ज़िले के अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम आमाकड़ा में 'झलमलको लया-लयोर गोटुल रच्चा उत्सव' में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- इस उत्सव का आयोजन स्थानीय संस्कृति, परंपरा, लोकगीतों और लोकनृत्यों को संरक्षित करने के लिये किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आदिवासी युवाओं व युवतियों को अपनी संस्कृति, विरासत से जोड़कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाना है।
- गोटुल संस्कृति, मांदरी, रेला, हुल्की, कोलांग जैसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन लगभग आदिवासी समाज से विलुप्त हो रहे हैं, जिसे संरक्षित करने की जानकारी देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

नोट :

- झलमलको युवक-युवतियों को दिया हुआ उपनाम है। इसका संबंध उन आदिवासी युवा एवं युवतियों से है, जो विशेष गुण से परिपूर्ण तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें अपनी जनजाति, रीति-रिवाज़ों सहित संस्कृति व परंपरा का पूर्णत: ज्ञान होता है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने के साथ कोयलीबेड़ा में ज़िला सहकारी बैंक की स्थापना की भी घोषणा की।
- इसके आलावा स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिये अंतागढ़ क्षेत्र में 10 गोटुल और 10 देवगुड़ी निर्माण की भी घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने बस्तर में स्थापित 'बादल' की तरह कांकेर ज़िले में भी डांस, आर्ट और लिटरेचर को बढ़ावा देने, संगठन बनाने तथा अंतागढ़ क्षेत्र के 14 युवाओं को कृषि एवं वनोपज के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के अध्ययन के लिये इंडोनेशिया के अध्ययन दौरे पर भेजने की भी स्वीकृति प्रदान की।

शिवरीनारायण में राज्यस्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

8 से 10 अप्रैल, 2022 तक आयोजित तीन दिवसीय राज्यस्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत डॉ. राम सुंदर दास ने जांजगीर-चांपा ज़िले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल शिवरीनारायण के मेला ग्राउंड में शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यस्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता में 25 ज़िलों की चयनित मानस मंडलियों के लगभग 350 कलाकार इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे।
- इस प्रतियोगिता में विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।

बारनवापारा अभयारण्य को मिला नया स्वरूप

चर्चा में क्यों ?

8 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ का सबसे उत्कृष्ट तथा आकर्षक अभयारण्य बारनवापारा का नए स्वरूप में कायाकल्प हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- यह कायाकल्प वन्यप्राणी रहवास उन्नयन कार्य के अंतर्गत कैंपा (छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) की वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 में स्वीकृत राशि से किया गया है।
- इस वार्षिक कार्ययोजना के तहत 5 हज़ार 920 हेक्टेयर रकबे में सघन लेंटाना उन्मूलन तथा यूपोटोरियम उन्मूलन का कार्य हुआ है, जिसमें से बारनवापारा अभयारण्य के 19 कक्षों में कुल 950 हेक्टेयर रकबे में लेंटाना उन्मूलन का कार्य और 32 कक्षों में कुल 4 हज़ार 970 हेक्टेयर रकबे में यूपोटोरियम उन्मूलन का कार्य शामिल है।
- राजधानी रायपुर से लगभग 100 किमी. की दूरी पर बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत स्थित बारनवापारा अभयारण्य में हुए वन्यप्राणी रहवास उन्नयन कार्य से वहाँ मृदा में नमी होने के कारण घास प्रजाति शीघ्रता से बढ़ने लगी है। साथ ही इससे अभयारण्य में वन्यप्राणियों को अब घास चरने के लिये अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे वे लेंटाना तथा यूपोटोरियम के उन्मूलन कार्य के बाद स्वच्छंद विचरण भी करने लगे हैं। इससे पर्यटकों को वन्यप्राणियों की सहजता से दृष्टता हुई है और वन्यप्राणी भी स्वस्थ व तंदुरुस्त दिखाई देने लगे हैं।
- गौरतलब है कि बारनवापारा अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 244.86 वर्ग किमी. है, जिसमें मुख्यत: मिश्रित वन, साल वन व पूर्व के सागौन वृक्षारोपण हैं। बारनवापारा में मुख्य रूप से कर्रा, भिर्रा, सेन्हा मिश्रित वनों में पाए जाते हैं। सागौन वृक्षारोपण क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगे सागौन हैं तथा साल वन क्षेत्र कम रकबे में हैं।

नोट :

- उक्त छत्रक प्रजाति के अतिरिक्त शाकीय प्रजाति, जैसे- यूपोटोरियम, लेंटाना, चरोठा आदि प्रमुख खरपतवार हैं, जिनके कारण बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र में पाए जाने वाले शाकाहारी वन्यप्राणियों को घास नहीं मिलती, वन्यप्राणियों को आवागमन में भी दिक्कत होती है तथा माँसभक्षी प्राणियों से भी बचाव कठिन हो जाता है।
- उल्लेखनीय है कि बारनवापारा अभयारण्य में तेंदुए, गौर, भालू, साँभर, चीतल, नीलगाय, कोटरी, चौसिंघा, जंगली सूअर, जंगली कुत्ता, धारीदार लकड़बग्घा, लोमड़ी, भेड़िया एवं मूषक मृग जैसे वन्यप्राणी बहुतायत में मिलते हैं एवं आसानी से दिखते भी हैं।

रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ में विकसित किये जा रहे राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत जाँजगीर-चांपा ज़िले के शिवरीनारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर में रामायणकालीन घटनाओं और वनवास काल के दौरान श्रीराम के द्वारा पैदल तय किये गए स्थानों के बारे में पेंटिंग्स के ज़रिये चित्रित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
- इन पेंटिंग्स के ज़रिये आने वाली भावी पीढ़ी को रामायणकालीन घटनाओं की जानकारी मिल सकेगी तथा लोग शिवरीनारायण की ऐतिहासिकता को भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे।
- 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का कुल क्षेत्रफल 6000 स्क्वायर फीट है। इसे 40 × 50 फीट के दो हॉल में बांटा गया है। एक हॉल में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर के साथ ही पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित है।
- रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर के बाहर ही माता शबरी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसमें वह भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाती हुई नज़र आ रही हैं। भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण की भी मूर्ति स्थापित की गई है।
- राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरीनारायण में स्थापित रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर पर्यटकों के लिये आकर्षण का केंद्र होगा तथा इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ को भी बढ़ावा मिलेगा।

राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत शिवरीनारायण में प्रथम चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामनवमी के अवसर पर महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों के संगम पर स्थित छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल शिवरीनारायण में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए प्रथम चरण के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम से जुड़ी स्मृतियों को सहेजते हुए यहाँ की संस्कृति को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिये प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना शुरू की है।
- इस परियोजना के पहले चरण में विकास के लिये चुने गए 9 में से 2 स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो गया है। इनमें से माँ कौशल्या धाम चंदखुरी के विकास कार्यों का लोकार्पण 7 अक्टूबर, 2021 को किया गया था।
- श्रद्धालुओं को दीप प्रज्वलित करने में परेशानी न हो, इसके लिये मंदिर परिसर के भीतर ही विशाल दीप स्तंभ का निर्माण किया गया है।
- शिवरीनारायण प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण नगर है, जो छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी धाम के नाम से विख्यात है।
- श्रद्धा के साथ ही यह संगम तट पर्यटन के लिये भी जाना जाए, इसके लिये घाट पर व्यू प्वॉइंट का निर्माण किया गया है, जहाँ से पर्यटकों को अद्भुत नज़ारों का दीदार होगा।

नोट :

- पौराणिक मान्यता के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु राम ने लगभग 10 वर्ष का समय छत्तीसगढ़ में गुज़ारा था। वनवास काल में उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका से किया था। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वे छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों से गुज़रे। सुकमा का रामाराम उनका अंतिम पड़ाव था।
- प्रभु राम ने वनवास काल के दौरान लगभग 2260 किमी. की यात्रा की थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ से जुड़ी भगवान राम के वनवास काल की स्मृतियों को सहेजने तथा संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना वर्ष 2019 में चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में भूमि पूजन कर शुरू की गई थी।
- परियोजना के तहत चयनित 75 स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार पहुँच मार्ग का उन्नयन, संकेत बोर्ड, पर्यटक सुविधा केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर, वैदिक विलेज, पगोड़ा वेटिंग शेड, मूलभूत सुविधा, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, सिटिंग बेंच, रेस्टोरेंट, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण आदि कार्य कराए जाएंगे।
- शिवरीनारायण महत्ता इस बात से पता चलती है कि देश के चार प्रमुख धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम् के बाद इसे पाँचवें धाम की संज्ञा दी गई है।
- यह स्थान भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान है, इसलिये छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रभु राम का नारायणी रूप गुप्त रूप से विराजमान है, इसलिये यह गुप्त तीर्थधाम या गुप्त प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है।
- राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रथम चरण में सीतामढ़ी-हरचौका (ज़िला- कोरिया), रामगढ़ (ज़िला- सरगुजा), शिवरीनारायण (ज़िला- जाँजगीर-चांपा), तुरतुरिया (ज़िला- बलौदाबाज़ार), चंदखुरी (ज़िला- रायपुर), राजिम (ज़िला- गरियाबंद), सप्तर्षि आश्रम सिहावा (ज़िला- धमतरी), जगदलपुर और रामाराम (ज़िला- सुकमा) को विकसित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के हिस्से फिर राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2022 को पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, 2022 के लिये ज़िला पंचायत कबीरधाम के साथ अन्य पंचायतों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किये गए विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर ज़िले का चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिये हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि कबीरधाम ज़िले में मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को बड़ी मात्रा में रोज़गार दिया गया। महिलाओं को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा गया, वहीं ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधोसंरचना विकास जैसे सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किये गए।
- इसी तरह ग्राम पंचायत केजेदाह का ग्रामीणों को अधिक-से-अधिक रोज़गार देने के साथ मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तथा दस्तावेजीकरण व पारदर्शिता के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाएगा।
- इन वर्गों में भी छतीसगढ़ की पंचायतों का चयन हुआ है-
- दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिये ज़िला वर्ग में ज़िला पंचायत कबीरधाम के साथ ब्लॉक वर्ग के लिये पाटन एवं सूरजपुर का चयन हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी ज़िले के ग्राम छिपली व हर्दीभाटा, कोरिया ज़िले के चिरमी, बालोद ज़िले के पैरी, सूरजपुर ज़िले के बसदई एवं कबीरधाम ज़िले के केजेदाह को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- इधर चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी में रायपुर ज़िले के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत बनचरौदा को पुरस्कृत किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग ज़िले के जेवरा को सम्मानित किया जाएगा। वहीं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिये रायपुर ज़िले के तिल्दा ब्लॉक अंतर्गत सरोरा को चुना गया है।

नोट :

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2022 को छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस फैसले से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। इस फैसले से लगभग तीन लाख अधिकारी-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से 1 नवंबर, 2004 तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी।
- वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार भविष्य निधि में 1 अप्रैल, 2022 से मूल वेतन से 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
- इसी प्रकार वर्ष 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिये की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती 1 अप्रैल, 2022 से समाप्त कर दी गई है।
- जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक् से रखा जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित होने पर यह राशि उसमें दर्शाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किया 'आईना-ए-छत्तीसगढ़' पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2022 को छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडेय की पुस्तक 'आईना-ए-छत्तीसगढ़' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडेय ने मुख्यमंत्री को बताया कि 'आईना-ए-छत्तीसगढ़' नाम से उनका कॉलम नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा है, जिनमें से चुनिंदा कॉलमों को अब पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है।
- इन कॉलमों में छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, सामाजिक घटनाक्रमों सहित छत्तीसगढ़ की दिनोदिन बदलती राजनीति, नौकरशाही सहित समसामयिक मुद्दों का समावेश किया गया है। यह उनकी पाँचवी पुस्तक है।

मुख्यमंत्री ने किया 'आईना-ए-छत्तीसगढ़' पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2022 को छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडेय की पुस्तक 'आईना-ए-छत्तीसगढ़' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडेय ने मुख्यमंत्री को बताया कि 'आईना-ए-छत्तीसगढ़' नाम से उनका कॉलम नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा है, जिनमें से चुनिंदा कॉलमों को अब पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है।
- इन कॉलमों में छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, सामाजिक घटनाक्रमों सहित छत्तीसगढ़ की दिनोदिन बदलती राजनीति, नौकरशाही सहित समसामयिक मुद्दों का समावेश किया गया है। यह उनकी पाँचवी पुस्तक है।

नोट :

राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, 2022

चर्चा में क्यों ?

17 अप्रैल, 2022 को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि 19 अप्रैल को रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के साथ-साथ राज्य स्तरीय कला एवं चित्रकला तथा आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्त्वावधान में किया जाएगा।
- लोक संस्कृति के संरक्षण एवं विकास से संबंधित पद्मश्री दमयंती बेसरा, पद्मश्री हलधर नाग, पद्मश्री साकी नेती रामचंद्रा (कोया जनजाति) इसके उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से शामिल होंगे।
- इस महोत्सव के प्रथम दिवस 19 अप्रैल को प्रथम सत्र में जनजातीय साहित्य भाषा विज्ञान एवं अनुवाद, जनजातीय साहित्य में जनजातीय अस्मिता एवं जनजातीय साहित्य में जनजातीय जीवन के चित्रण तथा जनजातीय समाजों की वाचिक परंपरा की प्रासंगिकता एवं जनजातीय साहित्य में अनेकता एवं चुनौतियों विषय पर शोधपत्र प्रस्तुत किये जाएंगे।
- द्वितीय दिवस 20 अप्रैल को जनजातीय साहित्य में लिंग संबंधी मुद्दे, जनजातीय कला साहित्य, जनजातीय साहित्य में सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष, जनजातीय साहित्य के मुद्दे, चुनौतियाँ एवं संभावना तथा जनजातीय विकास के मुद्दे एवं चुनौतियों पर शोध-पत्र प्रस्तुत किये जाएंगे।
- तृतीय दिवस 21 अप्रैल को पंचम सत्र में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका संघर्ष, भूमिका एवं योगदान) पर शोध-पत्र प्रस्तुत किये जाएंगे।
- महोत्सव में छत्तीसगढ़ के विभिन्न नृत्य विधाओं, जैसे- शैला, सरहुल, करमा, सोंदो, कुडुक, दशहरा करमा, विवाह नृत्य, मड़ई नृत्य, गरवसिंह गेड़ी, करसाड़, मांदरी, डंडार आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम के तहत प्रख्यात कलाकारों द्वारा जनजातीय संस्कृति एवं जनजातीय महापुरुषों एवं क्रांतिवीर, गुंडाधूर, शहीद वीर नारायण सिंह पर आधारित नाट्य मंचन किया जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना के हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत में कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रकाशन के साथ ही सूची के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ताकि ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्रसूची में दर्ज है, परंतु वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे प्रकरण में उनके वैध वारिसों से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार परीक्षण उपरांत उनका नाम पात्रसूची में जोड़ा जा सके।
- जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल हैं, परंतु उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कृषि भूमि अर्जित कर लेने के कारण योजना के अंतर्गत अपात्र हो गए हैं, ऐसे हितग्राहियों के संबंध में आपत्ति/पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची से विलोपित किया जा सकेगा।
- गौरतलब है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की गई है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मज़दूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। इसके सफल संचालन के लिये ज़िला अनुश्रवण समिति का भी गठन किया गया है।

नोट :

छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को मिला राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय एलेट्स आत्म निर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ शासन की महत्त्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड (Elets Innovations Award) से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि में इनोवेशन केटेगरी में यह अवार्ड प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक, सीईओ एवं एडिटर इन चीफ डॉ. रवि गुप्ता एवं टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव यू.पी. सिंह ने संयुक्त रूप से यह अवार्ड गोधन न्याय योजना के संयुक्त संचालक आर.एल. खरे को प्रदान किया।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिये 'स्कॉच गोल्ड अवार्ड' मिल चुका है। स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में यह अवार्ड प्रदान किया गया था।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 20 जुलाई, 2020 को हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीद की जा रही है।
- इस योजना से पशुधन संरक्षण और फसल संवर्द्धन एवं पर्यावरण की सुरक्षा, छुट्टा पशुओं पर नियंत्रण, गोबर विक्रय से ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आय, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद से महिला स्व सहायता समूहों को रोज़गार एवं आय का जरिया तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन मिला है। वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद के उपयोग से खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार और खेती की लागत में कमी आ रही है।
- इस योजना से डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी है।

छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को मिली जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर (सीजीओसर्ट) को जैविक उत्पाद का पंजीयन करने एवं देश की अधिकृत संस्था से परीक्षण कराकर जैविक उत्पाद के रूप में सर्टिफाइड करने की अनुमति कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (अपेडा) से प्राप्त हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ के कृषक अब राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में जैविक फसल के रूप में पंजीयन कराकर सर्टिफाइड फसल उपज का प्रदेश के बाहर एवं देश के बाहर विक्रय कर सकेंगे।
- छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के अपर संचालक ए.बी. आसना ने बताया कि जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता मिलने से राज्य के किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। विदेश में छत्तीसगढ़ राज्य के सुगंधित चावल, फोर्टिफाइड राइस, कोदो, कुटकी, रागी की डिमांड बढ़ी है।
- जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित सुगंधित चावल, कोदो, कुटकी, रागी का प्रमाणीकरण कराकर यदि विदेशों में इसकी सप्लाई की जाए, तो किसानों को 10 गुना से लेकर 100 गुना से भी अधिक कीमत मिलेगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा और देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक कृषि-प्रधान राज्य है। प्रदेश में लघु धान्य फसलों, जैसे- कोदो, रागी एवं कुटकी, सुगंधित चावल, जैसे- जीरा फूल, देवभोग, जवा फूल आदि का उत्पादन होता है।
- छत्तीसगढ़ के ऐसे जैविक कृषि उत्पादों की मांग देश एवं विदेशों में भी बहुत अधिक होने लगी है। जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता मिल जाने से किसानों को सुविधा होगी और इसका लाभ उठाकर किसान जैविक खेती की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे।

नोट :

छत्तीसगढ़ में 9240 करोड़ रुपए लागत की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 9240 करोड़ रुपए लागत की कुल 1017 किमी. लंबाई की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- राजधानी रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
- इन सड़कों के बनने से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के लिये सुचारु रोड नेटवर्क विकसित होगा। इससे ईंधन, यात्रा समय, दूरी और कुल परिवहन लागत में बचत होगी।
- केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के तीन मार्गों- रायगढ़-घरघोड़ा-धरमजयगढ़-पत्थलगाँव मार्ग (लंबाई 75 किमी.), अंबिकापुर-वाड्रफनगर-बंहनी-रेनकूट-बनारस मार्ग (लंबाई 110.60 किमी.) तथा पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग (लंबाई 37 किमी.) को भारतमाला परियोजना-2 में शामिल करने का आश्वासन दिया।
- केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह पर छत्तीसगढ़ में आरओबी निर्माण के लिये 300 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके अतिरिक्त आरओबी के लिये वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ को 400 करोड़ रुपए मिलेंगे।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से रायपुर से शदाणी दरबार तक 10 किमी. हिस्से में सर्विस रोड की स्वीकृति प्रदान करने, रायपुर शहर में टाटीबंध चौक से मैगनेटो मॉल के बीच फ्लाईओवर निर्माण, एनएच-30 में ग्राम धनेली से विधानसभा, बलौदाबाज़ार होते हुए सारंगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग को एनएच-53 से जोड़ने तथा विधानसभा से जोरा (एनएच-53) के इस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया।
- इसी तरह मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से राम वन गमन पथ (लंबाई 1000 किमी.), चंद्रपुर-खरसिया-पत्थलगाँव मार्ग, कुम्हारी-भिलाई बाइपास (लंबाई 23 किमी.) तथा बरदुला-नगरी-कांकेर-संबलपुर-मानपुर मार्ग (लंबाई 195 किमी.) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3525 किमी. है। इसमें से 2447 किमी. का लोक निर्माण विभाग तथा 1078 किमी. का एनएचएआई द्वारा संधारण एवं निर्माण किया जा रहा है।
- उन्होंने चांपा-उरगा-कोरबा मार्ग निर्माण, पाली-कटघोरा मार्ग निर्माण, मुंगेली-पोंडी मार्ग, झलमला-शेरपार-मानपुर मार्ग, अभनपुर-पोंड मार्ग, मदांगमुड़ा से देवभोग मार्ग के निर्माण की स्वीकृति देने तथा भारतमाला एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम मार्ग, बिलासपुर-उरगा-पत्थलगाँव मार्ग, चांपा-कोरबा मार्ग को शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री गडकरी को धन्यवाद दिया।

राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

19-21 अप्रैल, 2022 तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, राज्यस्तरीय जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं राज्यस्तरीय जनजाति कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता के तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसका आयोजन भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया गया।
- इस आयोजन के दौरान विविध कार्यक्रमों के साथ-साथ देश के प्रख्यात साहित्यकारों ने जनजातीय साहित्य और संस्कृति पर गहन विचार-विमर्श किया।

नोट :

- साहित्य महोत्सव के अंतर्गत साहित्य परिचर्चा एवं शोध-पत्र वाचन किया गया। साहित्य परिचर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 08 सत्र आयोजित किये गए, जिसमें देश के प्रख्यात साहित्यकारों ने भाग लिया।
- इसके अंतर्गत भारत जनजातीय भाषा एवं साहित्य का विकास- वर्तमान एवं भविष्य, भारत में जनजातीय विकास- मुद्दे, चुनौतियाँ एवं भविष्य, भारत में जनजातियों में वाचिक परंपरा के तत्त्व एवं विशेषताएँ तथा संरक्षण हेतु उपाय, भारत में जनजातीय धर्म एवं दर्शन, जनजातीय लोक कथाओं का पठन एवं अनुवाद तथा विभिन्न बोली-भाषाओं में जनजातीय लोक काव्य पठन एवं अनुवाद आदि विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया।
- इसी प्रकार शोध-पत्र वाचन में जनजातीय साहित्य: भाषा विज्ञान एवं अनुवाद, जनजातीय साहित्य में जनजातीय अस्मिता, जनजातीय साहित्य में जनजातीय जीवन का चित्रण, जनजातीय समाजों में वाचिक परंपरा की प्रासंगिकता, जनजातीय साहित्य में अनेकता एवं चुनौतियाँ, जनजातीय साहित्य में लिंग संबंधी मुद्दे, जनजातीय कला साहित्य, जनजातीय साहित्य में सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष, जनजातीय साहित्य में मुद्दे, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ तथा जनजातीय विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ विषय पर शोध-पत्र का वाचन किया गया।
- साहित्यिक शोध-पत्र पठन एवं जनजातीय साहित्य पर परिचर्चा के अलावा इस अवसर पर कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 30 आयु वर्ग एवं 30 से ऊपर प्रतिभागियों के लिये कैनवास पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- वहीं दूसरी ओर 12 से 18 आयु वर्ग के लिये ड्राइंग सीट पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- इसके अलावा हस्तकला प्रदर्शन के अंतर्गत बाँस कला, छिंदकला, गोदना कला, रजवार कला, शीसल कला, माटी कला एवं काष्ठ कला के प्रतिभागियों द्वारा अपनी प्रतिभा का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया।

'मोर गाँव मोर पानी' अभियान

चर्चा में क्यों ?

22 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'मोर गाँव मोर पानी' अभियान के समापन अवसर पर दुर्ग ज़िले के गंज मंडी प्रांगण में जल गुणवत्ता जाँच से जुड़ी महिलाओं को 'जल बहिनी' की उपाधि देकर उनका सम्मान किया।

प्रमुख बिंदु

- यह अभियान छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में यूनिसेफ के सहयोग से किया गया।
- इसकी शुरुआत जल जीवन मिशन के अंतर्गत 22 मार्च, 2022 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई थी।
- 22 मार्च से 22 अप्रैल तक चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम में वर्षा जल का विभिन्न तकनीकी विधियों से संवर्द्धन एवं जल के उपयोग उपरांत उत्पन्न ग्रे वाटर का उचित प्रबंध कर संपूर्ण जल का संवर्द्धन एवं संरक्षण करना है।

सीएसआई-एसआईजी का ई-गवर्नेंस अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2022 को प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 19वाँ सीएसआई-एसआईजी अवार्ड समारोह में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को सीएसआई-एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड स्कूली बच्चों के आंकलन एवं अभ्यास कार्य को आसान बनाने के लिये लागू टेली-प्रेक्टीज के लिये रिकग्निशन कैटेगरी में प्रदान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के आकलन एवं अभ्यास कार्य को आसान बनाने तथा आकलन की प्रक्रियाओं में आमतौर पर होने वाली विसंगतियों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से टेली-प्रेक्टीज नामक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

नोट :

- इसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को टेलीग्राम में एक समूह बनाकर कार्य करना होता है। बच्चों के समक्ष प्रश्न आते-जाते हैं, जिनका बिना समय गँवाए बच्चों को जवाब देना होता है। प्रत्येक बच्चे के ई-जवाब का अपनेआप अलग-अलग वीडियो बन जाता है। इन वीडियो को बाद में शिक्षक देखकर बच्चों का आकलन कर सकते हैं।
- टेली-प्रेक्टीज कार्यक्रम पूर्णत: छत्तीसगढ़ में एनआईसी छत्तीसगढ़ के सहयोग से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें उपयोग में लाए जाने वाले प्रश्न भी यहाँ के शिक्षक ही तैयार करते हैं।
- विभिन्न संस्थाओं ने राज्य में प्रचलित टेली-प्रेक्टीस को देखा है और उन्हें बच्चों के अभ्यास एवं शिक्षकों के आकलन संबंधी कार्यों को आसान करने हेतु उपयोगी पाया है।
- उल्लेखनीय है कि सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस में किये गए नवाचारों को स्वीकार करने के लिये दिया जाता है।

कॉमनवेल्थ और एशियाड में उतरेंगी छत्तीसगढ़ की आकर्षि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ की उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित चयन स्पर्धा में महिला एकल में विजेता बनीं।

प्रमुख बिंदु

- चयन स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण आकर्षि कश्यप का अब इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 और एशियन गेम्स, 2022 में भाग लेना तय हो गया है।
- इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आकर्षि भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधू के साथ हिस्सा लेंगी।
- एशियाड और कॉमनवेल्थ के अलावा आकर्षि को उबेर कप 2022 में भी खेलने का मौका मिलेगा।
- गौरतलब है कि महिला एकल चयन स्पर्धा के फाइनल मैच में आकर्षि ने अश्मिता चालिहा को तीन सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाएँ पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केटेगरी में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिये तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक चेन्नई को प्रथम, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विजयवाड़ा को द्वितीय और तेलंगाना स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक हैदराबाद को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।
- इस अवसर पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष एम. झांसीरानी और एमडी अपेक्स बैंक आंध्र प्रदेश डॉ. रेड्डी को विशेष पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया।
- इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ओवर ऑल परफॉर्मेंस अवार्ड का प्रथम पुरस्कार केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तिरुवनंतपुरम, द्वितीय पुरस्कार असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक गुवाहाटी और तृतीय पुरस्कार सिक्किम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक गंगटोक को दिया गया।
- डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की केटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस का प्रथम पुरस्कार संयुक्त रूप से करीम नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक तेलंगाना और कर्नाटका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धारवाड़, द्वितीय पुरस्कार संयुक्त रूप से अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक गुजरात और राजकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गुजरात तथा तृतीय पुरस्कार सालेम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तमिलनाडु को प्रदान किया गया।

नोट :

- प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी क्षेत्र में सुभाष यादव अवार्ड का प्रथम पुरस्कार एम.एम. 137 अलावायल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पुडुकोट्टी तमिलनाडु को प्रदान किया गया।
- नेफस्कॉब अवार्ड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये द्वितीय पुरस्कार संयुक्त रूप से संधोल एग्री सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल प्रदेश और तिमिरी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक केरल तथा तृतीय पुरस्कार चोप्पाडांडी करीम नगर तेलंगाना को प्रदान किया गया।
- एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रथम पुरस्कार हिमाचल प्रदेश, द्वितीय पुरस्कार पंजाब और तृतीय पुरस्कार तेलंगाना को प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ को मलेरिया के मामलों में कमी के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को विश्व मलेरिया दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को मलेरिया के मामलों में गिरावट के लिये सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ. सुभाष मिश्रा ने नई दिल्ली में राज्य शासन की तरफ से यह सम्मान ग्रहण किया।
- मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर से एपीआई दर (Annual Parasite Incidence, यानी प्रति एक हज़ार की आबादी में सालाना मिलने वाले मलेरिया के मरीज़ों की संख्या) में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2018 में जहाँ प्रदेश की एपीआई, 2.63 थी, वहीं 2021 में घटकर 0.92 पर पहुँच गई है।
- गौरतलब है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा जनवरी-फरवरी 2020 में बस्तर संभाग के सातों आकांक्षी ज़िलों में 'मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान' का पहला चरण संचालित किया गया था।
- घर-घर जाकर पहले चरण में 14 लाख छह हज़ार, दूसरे चरण में 23 लाख 75 हज़ार, तीसरे चरण में 15 लाख 70 हज़ार, चौथे चरण में 19 लाख 98 हज़ार एवं पाँचवे चरण में 14 लाख 36 हज़ार लोगों की मलेरिया जाँच की गई। वर्ष 2016 में 26.78 एपीआई वाले बस्तर संभाग की एपीआई 2021 में घटकर 7.07 पर पहुँच गई है।
- बस्तर संभाग में अभियान के अच्छे असर को देखते हुए 'मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान' के तहत इसे प्रदेश के कुल 21 ज़िलों में विस्तारित किया गया है। अभियान के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पाँचवे चरण में मलेरिया पॉजिटिविटी दर क्रमश: 4.6 प्रतिशत, 1.27 प्रतिशत, 1.03 प्रतिशत, 0.56 और 0.79 प्रतिशत दर्ज की गई है। अभियान के प्रभाव से मलेरिया के मामलों में लगातार कमी आ रही है।

स्वदेश दर्शन योजना: ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट पहला फेज पूर्ण

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत राज्य के वनांचल क्षेत्र में 'ट्राइबल टूरिज्म सर्किट' बनाने के प्रथम फेज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसकी लागत 94 करोड़ 23 लाख रुपए है।

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत जशपुर-कुनकुरी-कमलेश्वरपुर-मैनपाट-महेशपुर-कुरदर-सरोधा दादर-गंगरेल-नथियानवागाँव-कोण्डागाँव- जगदलपुर-चित्रकोट-तीरथगढ़ को 'ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट' बनाने के प्रथम फेस का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट के लिये चिह्नांकित जशपुर को एथनिक पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। वहीं कुनकुरी में मार्ग सुविधा केंद्र, कमलेश्वपुर में इको एथनिक डेस्टीनेशन, मैनपाट में इको एथनिक डेस्टीनेशन-पर्यटन सुविधाएँ, महेशपुर में मार्ग सुविधा केंद्र तथा कुरदर में इको टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित किया गया है।

नोट :

- इसी प्रकार सरोधा दादर में एथनिक पर्यटन ग्राम, गंगरेल में ईको एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन, नथियानवागाँव में मार्ग सुविधा केंद्र, कोंडागाँव में एथनिक पर्यटक ग्राम, जगदलपुर में एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन (लामनी पार्क-कैफैटेरिया पार्किंग), चित्रकोट में ईको एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन और तीरथगढ़ में ईको एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन (नेचर ट्रेल, सीढ़ियाँ रेलिंग) के रूप में विकसित किया गया है।
- स्वदेश दर्शन योजना फेस-2 के अंतर्गत इको टूरिज़्म सर्किट की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस सर्किट में चिल्फी घाटी, अचानकमार-अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगों डैम के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल किया गया है। प्रस्तावित योजना की लागत 81 करोड़ 26 लाख रुपए है।

राज्यपाल ने किया छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन के लिये प्रस्तुत विधेयक छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 के अनुसार भू-राजस्व संहिता के मूल अधिनियम की 12 धाराओं, अध्याय 7 की 48 धाराओं एवं अध्याय 14 की 16 धाराओं में संशोधन किया गया है।
- संशोधित विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 01 में बंदोबस्त आयुक्त के स्थान पर 'आयुक्त भू-अभिलेख' प्रतिस्थापित किया गया है। इसी प्रकार बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर 'ज़िला सर्वेक्षण अधिकारी' प्रतिस्थापित किया गया है।
- मूल अधिनियम के अध्याय 7 में शीर्षक 'नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त' के स्थान पर 'भू-सर्वेक्षण तथा भू-राजस्व निर्धारण' शब्द प्रतिस्थापित किया गया है।
- संशोधित विधेयक में नवीन धारा 178 ख का अंत:स्थापन किया गया है। इसके अनुसार तहसीलदार, खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों को सर्वप्रथम ई-नामांतरण पोर्टल में प्रविष्ट कर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा एवं आम सूचना या इश्तहार का प्रकाशन करेगा।
- किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर या तहसीलदार को प्रकरण, किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर, वह ऑनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई-राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा, अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल में की जाएगी।

छत्तीसगढ़ पुलिस के 11 जवान शूरवीर सम्मान से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जांबाज पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिये आयोजित कार्यक्रम में आरक्षक से लेकर टीआई रैंक तक के 11 पुलिसकर्मियों को शूरवीर सम्मान से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- सम्मान पाने वालों में उपनिरीक्षक जाकिर अली, महिला आरक्षक मनीषा यादव, सहायक उपनिरीक्षक भूपेश सिंह, प्रधान आरक्षक संदीप दीक्षित, प्रधान आरक्षक सरफराज चिश्ती, निरीक्षक रमन उसेंडी, उपनिरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उपनिरीक्षक मनोज राठौर, प्रधान आरक्षक सुशील पांडे, निरीक्षक विजय चेलक तथा निरीक्षक सुमतराम साहू शामिल हैं।
- गृहमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिये, ताकि आम जनता में उसके प्रति सम्मान दिखे और अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो।
- गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नक्सली इलाकों के लिये दिये गए सूत्र वाक्य 'विश्वास, विकास, सुरक्षा' की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर विगत 3 वर्षों में लगभग 2 हज़ार माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना स्वीकार किया है।

नोट :

हैबियस कॉर्पस रिट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षी मामले में कहा कि लापता व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन.के. चद्रवंशी ने ऐसे मामलों के संदर्भ में कहा कि ''लापता व्यक्तियों के मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के नियमित प्रावधानों के तहत दर्ज़ किये जाने हैं और संबंधित पुलिस अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित तरीके से इसकी जाँच करने के लिये बाध्य हैं।''
- उच्च न्यायालय ने कहा कि जो चीज सुसंगत रहती है वह यह है कि 'अवैध निरोध' का आधार स्थापित करना और इस तरह की किसी भी 'अवैध हिरासत' के बारे में एक मज़बूत संदेह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्थानांतरित करने के लिये एक शर्त है और संवैधानिक न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करेंगे, जहाँ 'अवैध हिरासत' के बारे में संदेह का कोई आरोप नहीं है।
- यूनियन ऑफ इंडिया बनाम युमनाम आनंद एम और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि ''संविधान के अनुच्छेद 21 में यह घोषित है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अत्यधिक तत्परता के साथ अवैध हिरासत के प्रश्न की जाँच करने के लिये एक मशीनरी की निश्चित रूप से आवश्यकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट इस प्रकृति का एक उपकरण है।''
- गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 रिट- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा का उल्लेख है।

तीनदिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगाँव ज़िले के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में तीनदिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ 51 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया तथा चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी के शिकार हुए राजनांदगाँव ज़िले के 17,127 निवेशकों को एक करोड़ 57 लाख रुपए की राशि वापस लौटाई।
- मुख्यमंत्री बघेल ने राजनांदगाँव ज़िले में 14 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से स्थापित 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण भी किया।
- उल्लेखनीय है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन 27 से 30 अप्रैल, 2022 तक किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के संस्थापक खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी तथा राजकुमारी इंदिरा को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया।
- गौरतलब है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय है, जो दृश्य और प्रदर्शन कला के लिये समर्पित है। यह भारत का एकमात्र संगीत एवं ललित कला का विश्वविद्यालय है।
- सन् 1956 में खैरागढ़ रियासत के तत्कालीन राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी ने संगीत एवं ललित कला विश्वविद्यालय खोलने के लिये अपना महल दान कर दिया था और अपनी बेटी 'इंदिरा' के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा था।

नोट :

अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा 'माटी पूजन दिवस'

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2022 को राज्य शासन द्वारा राज्य में अक्षय तृतीया को 'माटी पूजन दिवस' के रूप में मनाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का परिपालन करते हुए निर्देश जारी कर दिये गए।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये अनेक पहल कर रही है। इस कड़ी में मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन के लिये रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के साथ ही गो-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है।
- इसी उद्देश्य को ही आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष 3 मई को अक्षय तृतीया पर राज्य में 'माटी पूजन दिवस' मनाने का महा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है।
- आयोजन को लेकर जारी निर्देश के अनुसार इस अवसर पर राजधानी रायपुर में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं ज़िला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर परंपरागत रूप से माटी पूजन किया जाएगा।
- माटी पूजन कार्यक्रम में धरती माता की रक्षा की शपथ ली जाएगी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा।
- इन कार्यक्रमों में ज़िलों के प्रभारी मंत्री, विधायकगण, त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि सहित कृषक एवं नागरिक शामिल होंगे। पर्यावरण से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण आयोजन में सामाजिक संगठनों तथा विद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
- गौरतलब है कि अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में 'अक्ती' के नाम से भी जाना जाता है।

हथखोज में रेल इंडस्ट्रियल पार्क तथा भिलाई में विभिन्न अधोसंरचनाओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

28 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित हथखोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क एवं भारी व हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में निर्मित अधोसंरचनाओं का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि रेल पार्क में 22 भूखंड हैं। रेल पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- रेल इंडस्ट्रियल पार्क से यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों का तेज़ी से विस्तार होगा। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर होने का लाभ रेलवे के लिये उपकरण तैयार करने वाली यूनिटों को होगा।
- एक ही जगह पर अधोसंरचना उपलब्ध होने का लाभ उद्यमियों को होगा तथा रेलवे के लिये भी रेल पार्क बन जाने से आसानी होगी।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हल्के एवं भारी औद्योगिक क्षेत्र में सवा चार किलोमीटर सीसी रोड का लोकार्पण भी किया गया। इसकी लागत 12 करोड़ रुपए है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 167 एमओयू किये हैं। इनके माध्यम से 78 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में प्रस्तावित है, इनमें 90 इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है।

नोट :

राज्य में खुलेंगे 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय

चर्चा में क्यों ?

28 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में खोले जा रहे एकलव्य विद्यालयों में छात्रों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 50 नए एकलव्य विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत किये गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठी से बारहवीं तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।
- छत्तीसगढ़ में 17 ज़िलों- बलरामपुर, बीजापुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बस्तर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, जशपुर, कोंडागाँव, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगाँव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, कांकेर और नारायणपुर में इन 50 एकलव्य विद्यालयों का स्थापना की जा रही है।
- ये 50 एकलव्य विद्यालय हैं-
- बलरामपुर में - ग्राम बरतीकला, रामनगर, देवीगंग, दोहना और बुड़ा बगीचा (नवापारा) में
- बीजापुर में - नुकनपाल, रुद्राराम और दुगईगुड़ा में
- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में - लाटा और नेवसा पेंड्रारोड में
- बस्तर में - मेटावाड़ा कोयेपाल, गोटिया, कोडेनार और छिंदावाड़ा में
- दंतेवाड़ा में - मेटापाल, हारम और कुआकोंडा में
- गरियाबंद में - गिरहोला में
- जशपुर में - घोलेंग, रैरूमाकला (सुखरापारा), धुंधरूडांड, कर्दना और पंडरीपानी में
- कोंडागाँव में - बेड़मा, कोरगाँव, शामपुर और चिचाड़ी में
- कोरबा में - लाफा और रामपुर में
- कोरिया में - घुघरा और जामथान में
- रायगढ़ में - बयासी, छत्तनगढ़ और पोटरा में
- राजनांदगाँव में - खवाशफाकड़ी और माडिंग-पिंडलिंग धेनु में
- सुकमा में - ऐराबोर और बालाटिकरा (छिंदगढ़) में
- सूरजपुर में - खोरमा, पालदानोली और बकिरमा में
- सरगुजा में - रिखी, सहानपुर, पेटला और शिवपुर में
- कांकेर में - अंजनी, फरसकोट, हिलचुर और नरहरपुर में
- नारायणपुर में - ओरछा में

छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों ?

29 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीज़ों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के पाँच सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र पाने वाले पाँच सरकारी अस्पतालों में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।

नोट :

- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले के आमाडांड, बस्तर के आड़ावाल और कांकेर के कोटतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा रायपुर के भाठागाँव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दुर्ग ज़िले के टंकी मरोदा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।
- गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा विगत मार्च महीने में इन पाँचों अस्पतालों का निरीक्षण कर वहाँ मरीज़ों के लिये उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया था। उन्होंने इस संबंध में मरीज़ों से भी फीडबैक लिया था।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्य के अस्पतालों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और मरीज़ों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्यकर्मियों के नियमित प्रशिक्षण के बाद संस्था का आंतरिक तथा राज्यस्तरीय मूल्यांकन, सेवा प्रदान ऑडिट तथा पेशेंट संतुष्टि सर्वे की प्रक्रिया की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का कई मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

दृष्टि The Vision

नोट :